

फ्री ई-बुक

 oliveboard

केंद्रीय बजट 2022-23

महत्वपूर्ण
बिंदु



बैंक, एसएससी, रेलवे और अन्य सरकारी परीक्षाओं

बजट के बारे में:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, यह उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। इसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है।

इसे मोटे तौर पर 2 खंडों में वर्गीकृत किया गया है- राजस्व बजट और पूंजीगत बजट।

बजट डेटा के 3 सेट प्रदान करता है

- पिछले वर्ष का वास्तविक डेटा
- वर्तमान वर्ष का अनंतिम डेटा
- अगले वर्ष के बजटीय अनुमाना

बजट 2022-23 की मुख्य विशेषताएं:

वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को संसद में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया है और यहां हम केंद्रीय बजट 2022 पर मुफ्त ईबुक लेकर आये हैं। इस वर्ष 2019, 2020 और 2021 के बाद वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का चौथा बजट होगा। इस बार **#AatmanirbharBharatKaBudget** शब्द का उपयोग किया जा रहा है।

केंद्रीय बजट 2022-23 के महत्वपूर्ण स्तंभ:

अमृत काल में प्रवेश करते हुए, भारत की 25 साल लंबी लीड @100, 2022-23 का बजट चार प्राथमिकताओं के साथ विकास को गति प्रदान करता है:

1. पीएम गतिशक्ति
2. समावेशी विकास
3. उत्पादकता वृद्धि और निवेश, सूर्योदय के अवसर, ऊर्जा संक्रमण, और जलवायु कार्य
4. निवेश का वित्तपोषण

पीएम गतिशक्ति:

- पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के दायरे में आर्थिक परिवर्तन, निर्बाध मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और रसद दक्षता के लिए सात इंजन शामिल होंगे।
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में इन 7 इंजनों से संबंधित परियोजनाओं को पीएम गतिशक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा।
- सात इंजन हैं: सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग, रसद अवसंरचना।

सड़क परिवहन:

- 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 25000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा।
- राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए 20000 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे।

मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क

- चार स्थानों पर मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के कार्यान्वयन के लिए 2022-23 में पीपीपी मोड के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे।

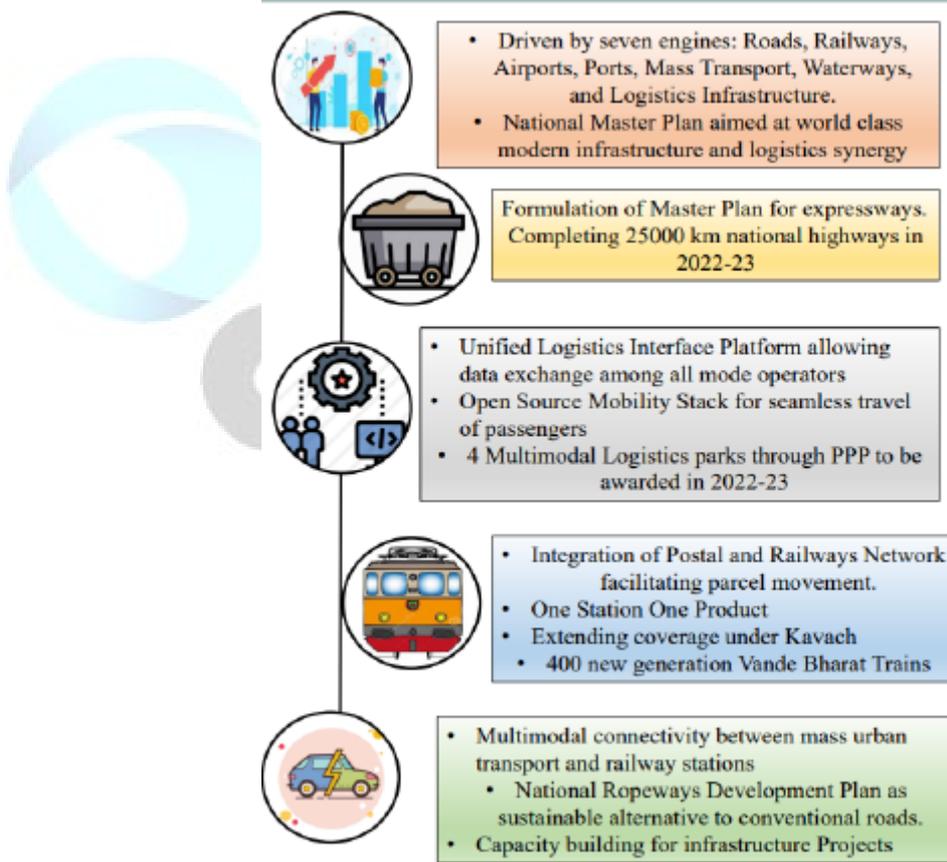
रेलवे

- स्थानीय व्यवसायों और आपूर्ति श्रृंखलाओं की सहायता के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट।
- 2022-23 में 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को क्वच, स्वदेशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और क्षमता वृद्धि के तहत लाया जाएगा।
- अगले तीन वर्षों के दौरान 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा।

- अगले तीन वर्षों के दौरान मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स के लिए 100 PM गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे

पर्वतमाला

- राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम, पर्वतमाला को पीपीपी मोड के अंतर्गत चलाया जाएगा
- 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबाई की 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे



समावेशी विकास

समावेशी विकास के तहत मुख्य फोकस क्षेत्र यहां दिए गए हैं।

1. हर घर, नल से जल: 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों को कवर किया जाएगा
2. पीएम आवास योजना: 2022-23 में 80 लाख घरों का निर्माण होगा
3. आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम: आकांक्षी जिलों के पिछड़े हुए ब्लॉकों का विकास किया जायेगा
4. डाकघरों द्वारा डिजिटल बैंकिंग: 100% डाकघर कोर बैंकिंग प्रणाली को जल्द से जल्द प्रयोग में लाएंगे
5. डिजिटल भुगतान: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करेंगे

PM-DevINE (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल)

1. पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं को निधि देने के लिए नई योजना PM-DevINE शुरू की गई
2. योजना के तहत युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम करने के लिए 1,500 करोड़ रुपये का प्रारंभिक आवंटन किया गया था

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम:

1. विकास लाभ से छूटे उत्तरी सीमा पर गांवों के लिए विकास का लक्ष्य है

ई-पासपोर्ट

1. एम्बेडेड चिप्स और फ्यूचरिस्टिक तकनीक के साथ ई-पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे।

रक्षा में आत्मा निर्भरत:

1. 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए पूंजीगत खरीद बजट को 68% तक बढ़ा दिया गया है, जो 2021-22 में 58% था।
2. रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25% रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट के साथ उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए खोला जाएगा।
3. परीक्षण और प्रमाणन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वतंत्र नोडल अम्ब्रेला बॉडी की स्थापना की जाएगी।

ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्य:

1. 2030 तक 280 GW स्थापित सौर ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 19,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा।
2. थर्मल पावर प्लांटों में पांच से सात प्रतिशत बायोमास पेलेट का को-फायर (co-fired) किया जाएगा:
 - A. सालाना 38 एमएमटी की CO2 बचत करना,
 - B. किसानों को अतिरिक्त आय और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना,
 - C. कृषि क्षेत्रों में पराली जलाने से बचने में मदद करें।
3. उद्योग के लिए कोयला गैसीकरण और कोयले को रसायनों में बदलने के लिए चार पायलट परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी।
4. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन किसानों को वित्तीय सहायता जो कृषि वानिकी को अपनाना चाहते हैं।

एमएसएमई क्षेत्र:

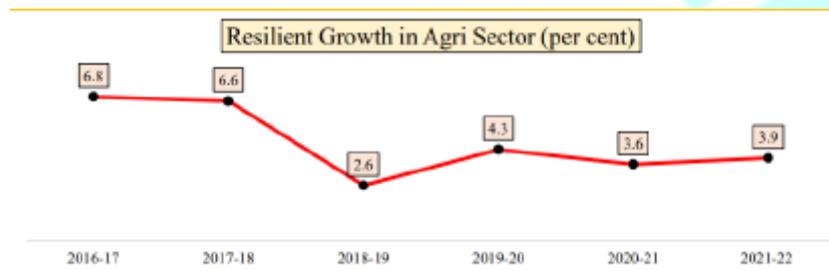
1. विभिन्न पोर्टलों को आपस में जोड़ा जाएगा (Udyam, e-shram, NCS and ASEEM)
2. आतिथ्य और संबंधित उद्यमों पर ध्यान देने के साथ ECLGS (आपातकालीन क्रेडिट लिंकड गारंटी योजना) का विस्तार करना
3. CGTMSE (सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट) में सुधार करना
4. MSME प्रदर्शन (आरएएमपी) बढ़ाने और तेज करने के लिए कार्यक्रम चलाएं जायेंगे

कृषि और खाद्य उत्पादन:

1. 1.63 करोड़ किसानों को गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपये का सीधा भुगतान किया जायेगा।
2. गंगा नदी के समीप भूमि वाले किसानों को रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना
3. बाजरे के उत्पादों की कटाई के बाद मूल्यवर्धन, खपत और ब्रांडिंग को बढ़ावा देना
4. पीपीपी मोड में किसानों को डिजिटल और हाई-टेक सेवाओं की डिलीवरी की जाएगी।
5. किसानों की सहायता के लिए किसान ड्रोन का उपयोग किया जायेगा।
6. कृषि स्टार्टअप्स को वित्तपोषित करने के लिए मिश्रित पूंजी के साथ फंड लॉन्च किया जायेगा।

केन-बेतवा लिंक परियोजना का कार्यान्वयन:

- केन बेतवा लिंक परियोजना के क्रियान्वयन से 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि लाभान्वित होंगे, 62 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध किया जायेगा और 130 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा।
- ऐसी 5 और परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में हैं।

**शिक्षा क्षेत्र:**

1. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जायेगा।
2. वन क्लास वन टीवी चैनल कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों तक विस्तारित किया जाएगा।

3. महत्वपूर्ण सोच कौशल को बढ़ावा देने और सीखने के वातावरण को प्रोत्साहित करने के लिए वर्चुअल लैब और स्किलिंग ई-लैब को स्थापित किया जायेगा।
4. विश्व स्तर की गुणवत्ता वाली सार्वभौमिक शिक्षा के साथ डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
5. डिजिटल शिक्षकों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली ई-सामग्री वितरित की जाएगी।

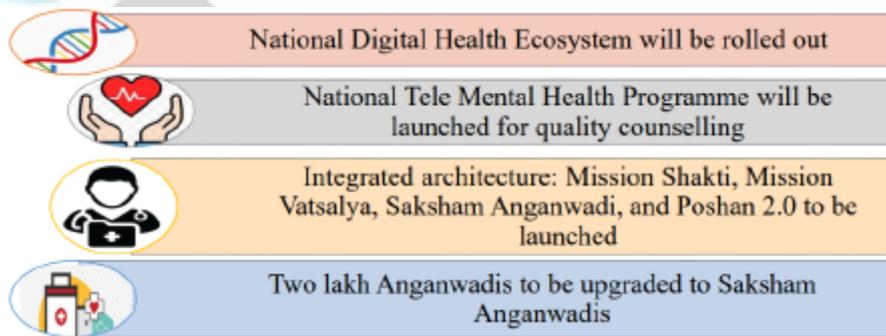
सक्षम आंगनवाड़ी

1. मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को एकीकृत लाभ पहुंचाया जाएगा।
2. दो लाख आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी में अपग्रेड किया जाएगा।

कौशल विकास:

1. ऑनलाइन प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड (DESH-Stack e-portal) शुरू किया जाएगा।
2. ड्रोन-एस-ए-सर्विस के लिए ड्रोन शक्ति की सुविधा के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा।

स्वास्थ्य



उत्पादकता वृद्धि और निवेश

व्यापार करने में आसानी	जीवन की सुगमता
<ul style="list-style-type: none"> • विश्वास आधारित शासन • IT पुलों के माध्यम से केंद्रीय और राज्य स्तरीय प्रणालियों का एकीकरण करना • PARIVESH पोर्टल के दायरे का विस्तार करना • भूमि अभिलेखों के आईटी आधारित प्रबंधन के लिए विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या • कंपनियों के स्वैच्छिक परिसमापन को सुविधाजनक बनाने के लिए C-PACE की स्थापना • End to end online e-Bill System and utilising surety bonds in government procurement. • AVCG प्रमोशन टास्क फोर्स • पीएलआई योजना के तहत 5जी को समर्थन • उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा जगत के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास को खोलना 	<ul style="list-style-type: none"> • चिप एम्बेडेड ई-पासपोर्ट जारी करना • भवन उपनियमों का आधुनिकीकरण, नगर नियोजन योजनाओं को लागू करना और पारगमन उन्मुख विकास करना • शहरी नियोजन में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना • शहरी क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के विकल्प के रूप में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी (battery swapping policy) प्रदान करना

निवेश का वित्तपोषण:

1. 2022-23 में प्रमुख निजी निवेश और मांग को जारी रखने के लिए सार्वजनिक निवेश किया जायेगा
2. 2022-23 से आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपये की शुरुआत की जाएगी
3. अगले वित्तीय वर्ष में पूंजीगत व्यय को 35.4% बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपये या सकल घरेलू उत्पाद का 2.9% कर दिया गया है, ताकि "निवेश के पुण्य चक्र" और निजी निवेश में भीड़ को किकस्टार्ट किया जा सके।
4. कैपेक्स आठ मंत्रालयों और विभागों में केंद्रित है, जिसमें परमाणु ऊर्जा कुल पूंजीगत व्यय का 1.9%, दूरसंचार 7.2%, रक्षा 20.3%, राज्यों को स्थानांतरण 14.9%, पुलिस 1.4%, आवास और शहरी मामले 3.6%, रेलवे 18.3 % और सड़क परिवहन और राजमार्ग 25.0% है।
5. 2022-23 के लिए राज्यों को GSDP के 4% के राजकोषीय घाटे की अनुमति दी जाएगी, जिसमें से 0.5% बिजली क्षेत्र के सुधारों से जुड़े होंगे।
6. पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता योजना के लिए परिव्यय में वृद्धि की जाएगी।

कर-प्रस्ताव:

1. ऋणियों को सुधारने के लिए करदाताओं को 2 वर्षों के भीतर अद्यतन विवरणी दाखिल करने की अनुमति दी गयी है।
2. विकलांग व्यक्तियों को कर में राहत दी जाएगी।
3. सहकारिताओं के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर दर और अधिभार को कम करना।
4. कर प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए पात्र स्टार्टअप को शामिल करने की अवधि बढ़ाना।
5. आभासी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30% कर लगेगा।
6. पुनरावृत्त अपील से बचने के लिए बेहतर मुकदमेबाजी प्रबंधन।
7. राज्य सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खाते में नियोजित के योगदान पर कर कटौती की सीमा में वृद्धि की गयी है।
8. आय और लाभ पर कोई अधिभार या उपकर व्यवसाय व्यय के रूप में स्वीकार्य नहीं है।
9. **SEZ (विशेष आर्थिक क्षेत्र)** में सीमा शुल्क प्रशासन पूरी तरह से आईटी संचालित होगा।
10. पूंजीगत वस्तुओं और परियोजना आयातों में रियायती दरों को धीरे-धीरे समाप्त करना और 7.5% का मध्यम टैरिफ लागू करना।
11. सीमा शुल्क छूट और टैरिफ सरलीकरण की समीक्षा करना।
12. घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण की सुविधा के लिए एक श्रेणीबद्ध दर संरचना प्रदान करने के लिए सीमा शुल्क दरों को अंशांकित किया जा रहा है।
13. भारत में निर्मित कृषि क्षेत्र के लिए उपकरणों के लिए छूट को युक्तिसंगत बनाना गया है।
14. स्टील स्क्रैप पर सीमा शुल्क छूट में वृद्धि की गयी है।
15. झींगा जलीय कृषि के लिए आवश्यक कुछ निविष्टियों पर शुल्क में कमी की गयी है।
16. मिश्रित ईंधन पर अतिरिक्त अंतर उत्पाद शुल्क लगेगा।

Foundation Course

for Bank & Insurance Exams 2022-23



Oliveboard

- 250+ Live Classes & Practice Sessions
- 280+ Mock, Sectional & Topic Tests
- Full Reasoning, Quant, Eng & GA Syllabus

40% OFF | Use Code: LAUNCH

Subscribe Now

केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं का आबंटन:

योजना का नाम	2021-22 में आवंटन	2022-23 में आवंटन
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	34947 Cr.	37800 Cr
जल जीवन मिशन	45011 Cr.	60000 Cr.
राष्ट्रीय शिक्षा मिशन	30796 Cr.	39553 Cr.
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	14000 Cr	19000 Cr.
पीएम किसान	67500 Cr	68000 Cr
आत्म निर्भर भारत रोजगार योजना	5000 Cr	6400 Cr
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	7400 Cr	10000 Cr

बजट 2022-23 से ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु:

वर्ष 2022-23 के लिए भारत की वृद्धि दर 9.27% होने का अनुमान है।

- 14 क्षेत्रों में PLI योजनाएं जिनमें 60 लाख नए रोजगार सृजित करने और 30 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त नए उत्पादन की संभावना है।
- उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 14 क्षेत्रों में 60 लाख नए रोजगार सृजित होंगे।
- जनवरी 2022 के महीने के लिए सकल जीएसटी संग्रह 1,40,986 करोड़ रुपये है – जो 2017 में कर की स्थापना के बाद से सबसे अधिक है।
- भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP)।
- अफगानिस्तान को विकास सहायता के लिए 200 करोड़ रुपये, चाबहार बंदरगाह के लिए 100 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
- केंद्रीय बजट 2022-23 में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के लिए आवंटन में कोई बढ़ोतरी नहीं, वित्त मंत्रालय ने इसे अगले वित्तीय वर्ष के लिए 73,000 करोड़ रुपये पर बरकरार रखा है।
- गृह मंत्रालय ((MHA) को 2022-23 के केंद्रीय बजट में 1.85 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है जो वर्तमान वित्त वर्ष के पिछले बजट में 1.66 लाख करोड़ रुपये के आवंटन से 11% अधिक है। 2019-20 में, बजट ने MHA को 1.67 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए थे।

यह भी देखें:

1. [Budget 2022-23 Live updates](#)
2. [Budget 2022-23 Key points](#)

FREE Ebooks

[Download Now](#)

Current Affairs

[Explore Now](#)

FREE MOCK TESTS + TOPIC TESTS + SECTIONAL TESTS

For Banking, Insurance, SSC & Railways Exams

[Web](#)

[APP](#)

BLOG

Your one-stop destination for all exam related information & preparation resources.

[Explore Now](#)

FORUM

Interact with peers & experts, exchange scores & improve your preparation.

[Explore Now](#)

